नंदिग्राम टाईम्स

RNI NO. MAHHIN/2016/69743 EDITOR : SHAIKH JAHUR AHEMAD

Thursday 15th January 2026 | ● वर्ष - 9 | ● अंक 260 | ● पृष्ठ 04 | ● मूल्य - 2 रूपए | ● www.nandigramtimes.com

मुंबई में 4 साल बाद बीएमसी चुनाव: सबसे बड़े बजट वाली महानगरपालिका में आज होगा मतदान

मुंबई — देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में चार साल की देरी के बाद आज बीएमसी (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) के चुनावों के लिए मतदान हो रहा है, जो शहर की जनता के लिए एक बड़ा लोकतांत्रिक पल है। इस चुनाव का महत्व इसलिए भी है क्योंकि बीएमसी सबसे बड़े बजट वाली महानगरपालिका मानी जाती है, जिसका वार्षिक बजट कई छोटे राज्यों के बजट से भी अधिक है।

मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा तक जारी रहेगा और शहर भर में लगभग 1 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यह मतदान 227 वार्डों के लिए हो रहा है जिसमें करीब 1,700 उम्मीदवार विभिन्न दलों और निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं।

बीएमसी पर पिछले कई दशकों से शिवसेना का प्रभुत्व रहा है, लेकिन इस बार राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना-यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे एकजुट होकर सत्ता बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा-शिंदे गुट भी पूरी ताकत से मुकाबला कर रहा है।

मतगणना 16 जनवरी 2026 को होने की संभावना है। बीएमसी चुनावों को लेकर सुरक्षा-व्यवस्था के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं और शहर में चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण रूप से संचालित करने की तैयारी है। मुंबईकरों की निगाहें न केवल स्थानीय प्रशासन के भविष्य पर हैं, बल्कि इस चुनाव का परिणाम राजनीतिक समीकरण और भविष्य की राजनीति पर भी प्रभाव डाल सकता है।

TOP NEWS | BJP Mission 2026: केरल में लेफ्ट का किला ढहाने की तैयारी

BJP Mission 2026: केरल में लेफ्ट का किला ढहाने की तैयारी, अमित शाह ने बनाया ये मास्टर प्लान

तिरुवनंतपुरम — 2026 केरल विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी को अपने मुख्य चुनावी मुद्दों में से एक के रूप में फैलाना शुरू कर दिया है, जिससे राज्य की राजनीतिक हवा और गरमाई है। भाजपा नेतृत्व का कहना है कि इस मामले ने केरल सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे "आस्था एवं सुशासन के प्रति विफलता" के रूप में जनता के सामने रखा जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में भाजपा के 'मिशन 2026' कार्यक्रम के दौरान कहा कि सोना चोरी मामला सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं है बल्कि मंदिर की आस्था और विश्वास का प्रश्न है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान प्राथमिकी (FIR) में ऐसे प्रावधान हैं जो कथित अपराधियों को बचाने के लिए किये गए हैं और निष्पक्ष जांच केवल किसी तटस्थ एजेंसी के हवाले करने से ही संभव होगी। भाजपा मांग कर रही है कि जांच सीबीआई या केंद्रीय एजेंसी के नियंत्रण में होनी चाहिए।

इस मुद्दे को भाजपा राजनीतिक मोर्चा पर भी

ले जा रही है और स्थानीय नेताओं ने 'साबरीमला संरक्षण ज्योति' के तहत राज्य भर में घरों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर दीप जलाने का आह्वान किया है, ताकि जनमानस में इस मुद्दे को व्यापक समर्थन मिल सके। विपक्षी दोनों फ्रंट — वाममोर्चा (LDF) और कांग्रेस-नेता यूडीएफ — पर भी भाजपा ने आरोप लगाये हैं कि वे आपस में मिलकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।

सबरीमाला सोना चोरी की जांच के सिलसिले में विशेष जांच दल (SIT) सक्रिय है और उसने मुख्य पुजारी कंदरारु राजीवरू समेत लगभग 11 से 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने भी इस मामले में पैसे की शेल्टरिंग का पैम्ला के तहत ECIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

केरल हाईकोर्ट सहित न्यायपालिका भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है। कोर्ट ने कहा है कि सारा मामला एक व्यापक और सुनियोजित साज़िश लगती है और इसे अलग-थलग घटना नहीं माना जा सकता, इसलिए जांच को और विस्तृत और स्वतंत्र बनाकर आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, सबरीमाला सोना चोरी मामला अब केरल के चुनावी परिदृश्य का एक गर्मागर्म मुद्दा बन गया है, जिस पर सभी पार्टियाँ अपने अपने एजेंडों को फिट कर रही हैं। भाजपा इसे राज्य सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में प्रचारित कर रही है, जबकि विपक्ष इसे भाजपा की चुनावी रणनीति के रूप में देख रहा है। इससे केरल चुनावों में धार्मिक भावनाओं, सुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर एक नई बहस उभर कर सामने आ गई है।

यह रणनीति यह संकेत देती है कि भाजपा केरल में राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए सबरीमाला सोना चोरी को केंद्र में रखकर चुनावी मैदान तैयार कर रही है, और इस मामले के निपटने के तरीके को राज्य की राजनीति के मुख्य पैमाने पर तौलने की कोशिश कर रही है।

लक्षद्वीप की 68 वर्षीय खालिदा बोली — "भारतीय नौसेना ने मेरे घर का नीला आसमान वापस दे दिया"

संवाददाता |

लक्षद्वीप — 68 वर्ष की खालिदा ने भावनात्मक रूप से कहा कि भारतीय नौसेना की सहायता से उन्हें अपने घर का "नीला आसमान" लौट आया है, एक मानवीय पहल जिसने उनके जीवन में खुशी फिर से जगाई। खालिदा का कहना था कि लंबे समय तक जीवन में कठिनाइयों के चलते सब कुछ फीका नजर आता था, लेकिन अब भारतीय नौसेना के विशेष शिविर और सेवाओं ने स्थानीय लोगों के लिए स्वास्थ्य, कल्याण और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की है।

भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के पांच द्वीपों पर व्यापक चिकित्सा और सहायक सेवाओं के साथ शिविर लगाए, जिसमें लोगों को मुफ्त चिकित्सा, परामर्श और जीवन शैली सहायता भी दी गई।

खालिदा ने कहा कि यह पहल केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि इससे भावनात्मक व मानसिक समर्थन भी मिला, जिससे उन्होंने फिर से खुश और जीवंत महसूस किया। यह कदम सरकार की दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य व कल्याण सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और स्थानीय निवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।

मीरा-भायंदर: चुनाव प्रचार खत्म होते ही शिंदे सेना दंपति पर मामला, बेटे सहित गिरफ्तार; भाजपा-शिंदे कार्यकर्ताओं में हंगामा

नवी मुंबई — मीरा-भायंदर महापालिका चुनाव प्रचार समाप्त होते ही राजनैतिक तनाव बढ़ गया है। रात्री घणसोली इलाके में शिंदे सेना और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की घटना के बाद शिंदे सेना के दंपति उम्मीदवार मनोहर व विनया मढवी तथा उनके बेटे करण मढवी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है और करण को गिरफ्तार किया गया है। मामला रबाळे पुलिस थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है, जहाँ दंपति उम्मीदवारों पर पुलिस के साथ वाद-विवाद करने और जांच में बाधा डालने का आरोप है।

घटना तब शुरू हुई जब ऐरोली सेक्टर-16 में स्थित भाजप कार्यालय के पास कुछ युवकों को मारहाण करते देखा गया। शिकायत मिलने पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बाळकृष्ण सावंत की टीम प्रशासनिक कार्रवाई के लिए पहुँची, लेकिन दंपति उम्मीदवारों ने पुलिस कर्मियों के साथ विवाद किया और जांच में व्यवधान डाला। इसके बाद पुलिस ने करण मढवी को हिरासत में लिया और अन्य आरोपियों के खिलाफ भी गुन्हा दर्ज किया।

पुलिस के अनुसार इस विवाद के कारण कुछ समय के लिए इलाके में तनाव का माहौल बन गया था, लेकिन सख्त पुलिस उपस्थिति से स्थिति नियंत्रण में आ गई। इससे पहले कोपरखैरणे और घणसोली इलाकों में भी शिंदे सेना और भाजपा के कार्यकर्त्ताओं के बीच झड़प की कई शिकायतें पुलिस के पास पहुंच चुकी थीं, जिनके चलते भी सतर्कता बढ़ा दी गई थी।

स्थानीय लोगों ने चुनाव प्रचार के तुरंत बाद इस तरह की हिंसात्मक घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है और प्रशासन से शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना सुनिश्चित करने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि वह स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

अरशद मदनी का आरोप: कांग्रेस की नीति ने संविधान और देश को किया नुकसान पहुँचाया

नई दिल्ली — जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कांग्रेस पर धर्म-आधारित राजनीति की प्रति लचीली नीति अपनाने का गंभीर आरोप लगाया है। मदनी का कहना है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में सांप्रदायिकता के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाया, जिससे वह सत्ता से बाहर हो गई और देश व संविधान दोनों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि 77 साल पहले महात्मा गांधी की हत्या के बाद सांप्रदायिकता को गंभीरता से रोका गया होता, तो देश को "विनाश" की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता।

मदनी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सांप्रदायिक ताकतों के साथ नरमी बरती और संविधान के अनुरूप कठोर कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण ये शक्तियाँ आज "और भी मजबूत" हो गईं। उन्होंने कहा कि आज लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान को जिस तरह "खुले तौर पर मिटाया जा रहा है", उसकी कल्पना आज़ादी के समय के नेताओं ने कभी नहीं की होगी। यह टिप्पणी राजनीतिक बहस को और गर्मा सकती है, क्योंकि मदनी का बयान धर्मनिरपेक्षता, इतिहास और कांग्रेस की नीतियों पर इंगलिश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने IPS शत्रुजीत सिंह कपूर, प्रवीण कुमार को BSF की कमान

नई दिल्ली — केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) का नया महानिदेशक (DG) नियुक्त किया है। वे मौजूदा DG प्रवीण कुमार की जगह लेंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक इस पद पर रहेंगे। शत्रुजीत कपूर 1990 बैच के हरियाणा कैडर अधिकारी हैं और हाल ही में हरियाणा के डीजीपी के पद से हटाए गए थे।

वहीं प्रवीण कुमार, जो 1993 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के IPS अधिकारी हैं, को सीमा सुरक्षा बल (BSF) का नया महानिदेशक बनाया गया है और वे 30 सितंबर 2030 तक इस ज़िम्मेदारी संभालेंगे। BSF भारत की अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करता है। इन नियुक्तियों का उद्देश्य सीमा सुरक्षा बलों में नेतृत्व को मजबूत करना बताया गया है, खासकर हिमालय और देश की सीमा निगरानी में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए।

महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव 2026: मुंबई और पुणे के बाद नागपुर तीसरा सबसे बड़ा, 3.48 करोड़ मतदाता और सियासी संघर्ष गरम

मुंबई | महाराष्ट्र — 15 जनवरी 2026 को राज्य भर में होने वाले नगरपालिका चुनाव से पहले मतदाता और राजनीतिक परिदृश्य की ताज़ा सांख्यिकी ने बड़ा ध्यान खींचा है। लोकमत की रिपोर्ट के अनुसार, मतदाता संख्या और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के मामले में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) निसंदेह शीर्ष पर है, जहाँ लगभग 1,03,44,315 मतदाता पंजीकृत हैं और पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 11.63 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। यह शहर मतदाता आधार और राजनीतिक गतिविधि की वजह से चुनाव का मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है।

पुणे महानगरपालिका (PMC) दूसरे स्थान पर है, जहाँ 3,551,854 मतदाता हैं और 1,955 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं — यह किसी भी नगर निकाय में सबसे अधिक उम्मीदवारों की संख्या है,

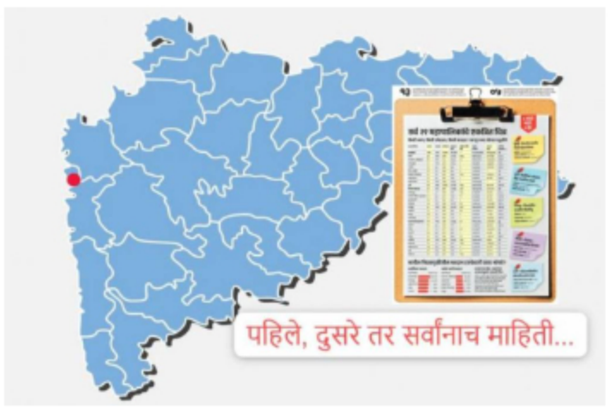

जो यहाँ की तीव्र प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है। राजनीतिक दलों के लिए पुणे में सघन प्रचार और रणनीति के दौर ने चुनावी माहौल को बेहद सक्रिय बना दिया है।

सबसे रोचक है कि राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर नागपुर (NMC) है, जहाँ 2,483,112 मतदाता मतदाता अधिसूची में पंजीकृत हैं और पिछले मौकों पर इसमें 389,720 की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विदर्भ के इस महत्वपूर्ण शहर की वोटर वृद्धि से राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है, खासकर जब नागपुर का आकार बड़े महानगरों के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है। राज्य के अन्य प्रमुख महानगर निकायों में पिंपरी-चिंचवड़, ठाणे, नाशिक, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार और छत्रपती संभाजीनगर शामिल हैं, जिनमें मतदाता वृद्धि और प्रत्याशी संख्या ने चुनावी प्रतिस्पर्धा को और तीव्र बनाया है।

पिंपरी-चिंचवड़ में मतदाता संख्या में 521,802 की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि ठाणे और नाशिक जैसे नगरों में भी सघन मतदाता आधार देखा गया है।

कुल मिलाकर 893 वार्डों में 2,869 नगरसेवक सीटें हैं और 3.48 करोड़ से अधिक मतदाता 15,931 उम्मीदवारों की भाग्य निर्णय करेंगे। मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा, जबकि मतगणना 16 जनवरी को तय है। सुरक्षा के मद्देनजर 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं ताकि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित हो सके।

विश्लेषकों के अनुसार यह चुनाव केवल स्थानीय निकायों के प्रशासनिक निर्णय का मैदान नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक ताकत, युवा मतदाताओं की भागीदारी, और शहरों के विकास एजेंडों के लिए गठबंधन समर्थन का भी निर्णायक मुकाबला बन चुका है।

ममता बनर्जी के खिलाफ ED का याचिका मामला आज सुना जाएगा: I-PAC छापेमारी विवाद हाईकोर्ट में गरमा गया

कोलकाता — कोलकाता उच्च न्यायालय में आज Enforcement Directorate (ED) की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हो रही है, जो I-PAC (Indian Political Action Committee) के दफ्तर और उसके निदेशक के निवास पर हुई छापेमारी से जुड़ी है। ED ने आरोप लगाया है कि 8 जनवरी को हुई I-PAC छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी और राज्य पुलिस ने जांच में बाधा डाली और महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा सामग्री अपने कब्जे में ले लिये, जिससे जांच प्रभावित हुई। ED अब CBI से स्वतंत्र जांच की भी मांग कर रहा है।

इस बीच, TMC ने अलग से याचिका दायर की थी जिसमें उसने राजनीतिक और चुनावी डेटा की सुरक्षा की मांग की थी, यह दावा करते हुए कि ED ने I-PAC की छापेमारी में पार्टी का संवेदनशील डेटा जब्त किया। लेकिन उच्च न्यायालय ने आज TMC की याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि ED ने स्पष्ट किया कि 8 जनवरी की छापेमारी में उसने किसी भी दस्तावेज़ या डिजिटल डेटा को जब्त नहीं किया। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे में डेटा की सुरक्षा का मुद्दा आगे बढ़ाने का कोई कारण नहीं बचता।

उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि ED की याचिका में सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में पहले से दायर समान याचिका के कारण आगे बढ़ाना उपयुक्त है, जिससे यह मामला अब मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विवादित विषय बन गया है।

यह मामला राजनीतिक और कानूनी रूप से संवेदनशील बना हुआ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं तथा I-PAC राजनीतिक रणनीति में शामिल रहा है। दोनों पक्षों की दलीलें और आरोप चुनावी माहौल को और गरमाए हुए हैं।

आज महाराष्ट्र के महानगरों में मतदान: शहरी लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी

संपादकीय अग्रलेख |

आज, 15 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के शहरी लोकतंत्र के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। राज्य की विभिन्न महानगरपालिकाओं में नगरसेवकों के चुनाव हेतु मतदान संपन्न हो रहा है। यह चुनाव केवल स्थानीय प्रतिनिधियों के चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात का जनादेश भी है कि महाराष्ट्र का शहरी नागरिक अपने शहरों को किस दिशा में ले जाना चाहता है।

भारतीय संविधान के 74वें संशोधन द्वारा महानगरपालिकाओं को स्थानीय स्वशासन की सशक्त इकाई के रूप में मान्यता दी गई है। पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, सड़कें, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएँ, प्राथमिक शिक्षा, शहरी नियोजन और पर्यावरण संरक्षण जैसी बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ महानगरपालिकाओं के माध्यम से ही निभाई जाती हैं। ऐसे में इन चुनावों का महत्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है।

महाराष्ट्र की महानगरपालिकाएँ और चुनाव

महाराष्ट्र राज्य में कार्यरत प्रमुख महानगरपालिकाओं में मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भायंदर, वसई-विरार, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपुर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, नागपुर, नाशिक, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद), सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली-मिरज-कुपवाड़, अमरावती, अकोला, जलगांव, लातूर, नांदेड-वाघाळा, परभणी, धाराशिव (उस्मानाबाद), चंद्रपुर, अहिल्यानगर (अहमदनगर), इचलकरंजी, मालेगांव और धुले जैसी महानगरपालिकाएँ शामिल हैं। ये शहर न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था की धुरी हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महाराष्ट्र की पहचान हैं।

निर्वाचन आयोग की भूमिका

राज्य निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र ने इन चुनावों के लिए निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु व्यापक इंतज़ाम किए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी, आदर्श आचार संहिता का सख़्ती से पालन, मतदान के दिन निषेधाज्ञा और मद्यविक्री पर प्रतिबंध जैसे कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं।

मतदान सुबह निर्धारित समय पर प्रारंभ होकर शाम तक चलेगा। आयोग द्वारा मतदाताओं से अपील की गई है कि वे भय, प्रलोभन या अफ़वाहों से दूर रहकर निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

मतदाता की भूमिका सबसे अहम

लोकतंत्र की मजबूती केवल क़ानूनों और व्यवस्थाओं से नहीं, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से सुनिश्चित होती है। शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहना लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। आज का दिन इस धारणा को बदलने का अवसर है।

शिक्षित, जागरूक और सुविधासंपन्न वर्ग यदि मतदान से दूर रहता है, तो निर्णय का भार सीमित सहभागिता पर आ जाता है। महानगरों की जटिल समस्याओं—जैसे ट्रैफिक जाम, कचरा प्रबंधन, जल संकट, प्रदूषण, अनियोजित विकास और भ्रष्टाचार—का समाधान तभी संभव है जब नागरिक सही प्रतिनिधियों का चयन करें।

राजनीतिक दलों के लिए स्पष्ट संदेश

महानगरपालिका चुनावों को अक्सर सत्ता की रिहर्सल के रूप में देखा जाता है, किंतु वास्तव में यह प्रशासनिक क्षमता की परीक्षा होते हैं। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि शहरी मतदाता केवल भाषणों और नारों से संतुष्ट नहीं होता। उसे पारदर्शी प्रशासन, समयबद्ध सेवाएँ और जवाबदेह नेतृत्व चाहिए।

आज का मतदान यह तय करेगा कि शहर विकास के नाम पर केवल कंक्रीट संरचनाओं तक सीमित रहेंगे या नागरिकों के लिए रहने योग्य, सुरक्षित और समावेशी बनेंगे।

शांति और कानून व्यवस्था

मतदान के दिन कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है, लेकिन नागरिकों का सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। किसी भी प्रकार की अफ़वाह, उकसावे या अवैध गतिविधि से दूर रहना और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

निष्कर्ष

15 जनवरी 2026 का यह मतदान दिवस महाराष्ट्र के शहरी भविष्य की दिशा तय करेगा। यह केवल एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आने वाले पाँच वर्षों की नीति, प्रशासन और विकास की नींव है। हर डाला गया वोट यह संदेश देता है कि नागरिक अपने शहर के प्रति सजग है और अपने अधिकारों व कर्तव्यों को समझता है।

लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार है और सबसे बड़ी शक्ति जागरूक नागरिक। आज यदि महाराष्ट्र का शहरी मतदाता जिम्मेदारी से मतदान करता है, तो यह न केवल महानगरपालिकाओं को मज़बूत करेगा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को भी नई ऊर्जा देगा।

आज का मतदान—शहरों के कल का निर्णय।

US Iran War: ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहा अमेरिका, 5 कारणों से समझें मजबूरी

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों को लेकर मुखर हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ईरान को मिलिट्री एक्शन की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती दिखाता है तो अमेरिकी सेना दखल देगी। ट्रंप की ये धमकियां वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद बढ़ गई है, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी समेत पकड़कर अमेरिका लाया गया था। हालांकि, ट्रंप की लगातार धमकियों के बावजूद ईरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जबरदस्त बल प्रयोग कर रहा है, जिसमें आधिकारिक रूप से 2500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा बताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं।

1- ईरान के नजदीक अमेरिकी सैन्य तैनाती कमजोर

ट्रंप लगातार ईरान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि, पेंटागन ने अभी तक ईरान के करीब कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात नहीं किया है, जैसा कि वेनेजुएला के मामले में देखा गया था। पिछले साल इजरायल के साथ 12 दिनों के युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान की व्यापक घेराबंदी की थी और कम से कम दो एयरक्राफ्ट कैरियरों, एक लाख सैनिकों और एम्फीबियस असाल्ट ग्रुप को भी तैनात किया था। हालांकि, इतनी भारी-भरकम तैनाती के बावजूद अमेरिका ने सिर्फ स्टील्थ बमवर्षकों के जरिए हवाई हमला किया था और उसे भी सीधे अमेरिकी धरती से अंजाम दिया गया था।

2- अमेरिका के खाड़ी सहयोगी तैयार नहीं

अमेरिका के खाड़ी सहयोगी देश भी ईरान के खिलाफ हमले को लेकर अनिच्छुक हैं। ट्रंप की विदेश नीति से उन्हें भी डर है कि कहीं मुश्किल के समय अमेरिका उन्हें अकेला न छोड़ दे। इनमें जॉर्डन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और मिस्र जैसे देश शामिल हैं। हालांकि, इन देशों की अवाम भी यह नहीं चाहती है कि अमेरिका उनका इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करे। ऐसे में ये देश अपने अवाम के विरोध से बचने के लिए अमेरिका से कन्नी काट रहे हैं और ईरान के खिलाफ हमले को लेकर उदासीन बने हुए हैं। 3- अमेरिकी हमले का उल्टा असर

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है, तो इसका उल्टा असर होगा। यह हमला सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और ईरानी सरकार को घरेलू समर्थन जुटाने, आंतरिक विरोध प्रदर्शनों को गैर-कानूनी ठहराने और बाहरी खतरे के खिलाफ क्षेत्रीय गठबंधनों को मजबूत करने में मदद करेगा। ऐसे में अमेरिका को इस हमले का अंजाम भुगतना होगा और ईरान में तख्तापलट की उम्मीदें पूरी तरह से टूट जाएंगी।

4- लॉजिस्टिक की समस्या

ईरान के आसपास के इलाके में पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी सैनिकों की संख्या में कमी आई है। इससे ट्रंप के लिए सैन्य विकल्प और कम हो गए हैं। अगर अमेरिका अभी से सैन्य तैनाती बढ़ाने का फैसला करता है तो उसे हफ्ते-दो हफ्ते का समय लग सकता है। इतने दिनों में ईरान विरोध प्रदर्शनों को बिलकुल दबा सकता है, जिसके बाद हमला करने का कोई मतलब नहीं बचेगा।

5- अमेरिका को सहना होगा पलटवार

ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ, तो वह भी इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। हालांकि इज़राइल के साथ 12 दिन की लड़ाई में ईरान की मिलिट्री ताकत काफी कम हो गई थी। लेकिन, खबरों के मुताबिक ईरान ने सीमित मिसाइल क्षमता बनाए रखी है। ईरान के मुख्य लॉन्च साइट पहाड़ों में छिपे हुए हैं। ईरान इन्हें बड़े पैमाने पर विकसित कर रहा है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के पास लगभग 2,000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो अगर बड़ी संख्या में लॉन्च की जाएं तो अमेरिका और इजरायल दोनों के लिए खतरा बढ़ सकता है।

सेवा से साकार होती भक्ति की राह— 'हिंद-दी-चादर' श्री गुरु तेगबहादूर साहिबजी के 350वें शहीदी समागम में सहभागी बनें

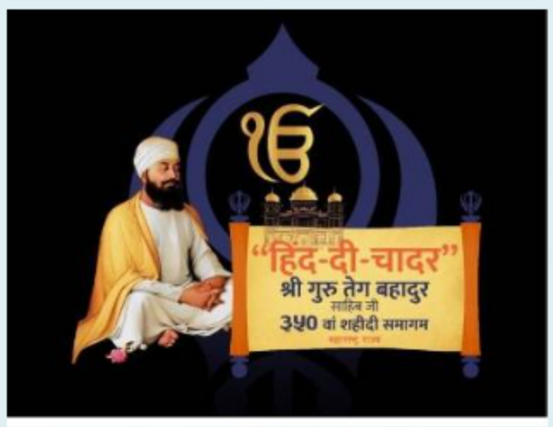

भारतीय इतिहास में धर्म, मानवता, त्याग और बलिदान के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में 'हिंद-दी-चादर' श्री गुरु तेगबहादूर साहिबजी का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। धर्म की स्वतंत्रता, मानवीय मूल्यों और सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले गुरु तेगबहादूर साहिबजी केवल सिख समुदाय के ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक रहे हैं।

उनकी महान शहादत के 350वें वर्ष के अवसर पर नांदेड शहर में 24 और 25 जनवरी 2026 को एक भव्य, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक शहीदी समागम का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सेवा, समानता और मानवता का विराट संगम होगा।

10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक उपस्थिति

यह ऐतिहासिक समागम असर्जन परिसर स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के लगभग 53 एकड़ विस्तीर्ण मैदान में आयोजित किया जाएगा। देश-विदेश से 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के नांदेड पहुंचने की संभावना है। इतनी विशाल संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति इस आयोजन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाएगी।

नौ समाजों की अभूतपूर्व एकजुटता

इस शहीदी समागम का आयोजन नौ समाजों के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है।
राज्य शासन का अल्पसंख्यक विभाग,
"हिंद-दी-चादर" श्री गुरु तेगबहादूर साहिबजी 350वीं शहीदी समागम समिति तथा
सिख, सिकलीकर, बंजारा, लबाना, मोहियाल, सिंधी, वाल्मिकी, उदासीन संप्रदाय और भगत नामदेव वारकरी समाज—सभी समाजों ने एक साथ आकर एकता और समता का आदर्श प्रस्तुत किया है।

यह संयुक्त आयोजन गुरु तेगबहादूर साहिबजी के उस संदेश को सजीव करता है, जिसमें कहा गया है—"सभी धर्म समान हैं और सभी मानव समान हैं।"

मुख्य मंडप और अनवाणी चलने की परंपरा

कार्यक्रम स्थल पर भव्य मुख्य मंडप का निर्माण किया जा रहा है, जहां दोनों दिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पावन प्रकाश रहेगा। गुरु के दर्शन के लिए आने वाले सभी श्रद्धालु, अतिथि, पदाधिकारी और गणमान्य व्यक्ति अनवाणी होकर मंडप तक पहुंचेंगे।

यह परंपरा अहंकार त्याग, नम्रता और गुरु चरणों में पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालुओं का अनवाणी चलकर गुरु के दर्शन के लिए आगे बढ़ना, सेवा से जुड़ी भक्ति का जीवंत उदाहरण होगा।
साथ ही, संत शिरोमणि श्री नामदेव महाराज के जन्मस्थान नरसी नामदेव से वारकरी दिंडियां पैदल यात्रा करते हुए नांदेड पहुंचेंगी।

श्रमदान से सजी सेवा संस्कृति

कार्यक्रम की तैयारियों के अंतर्गत हाल ही में भव्य श्रमदान अभियान संपन्न हुआ। नांदेड के जिलाधिकारी राहुल कर्डिले की उपस्थिति में प्रशासन, विद्यार्थी, स्वयंसेवक और श्रद्धालुओं ने मिलकर मैदान की सफाई, पत्थरों को हटाने और सुरक्षित मार्ग तैयार करने का कार्य किया।

यह श्रमदान गुरु तेगबहादूर साहिबजी की उस शिक्षा का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसमें सेवा को ही सर्वोच्च साधना बताया गया है।

लंगर: समानता और मानवता का जीवंत स्वरूप

समागम के दौरान श्रद्धालुओं के लिए 12 भव्य लंगर लगाए जाएंगे। प्रत्येक लंगर में एक समय में लगभग 3,000 श्रद्धालु बैठकर भोजन कर सकेंगे।
24 और 25 जनवरी को ये लंगर सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक निरंतर संचालित रहेंगे।

लंगर केवल भोजन व्यवस्था नहीं, बल्कि समानता का संदेश है—जहां जाति, धर्म, भाषा, देश या आर्थिक स्थिति का कोई भेद नहीं होगा। सभी श्रद्धालु एक पंक्ति में बैठकर गुरु का प्रसाद ग्रहण करेंगे।

निःशुल्क सेवा स्टॉल और जूता-घर व्यवस्था

कार्यक्रम स्थल के चारों ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में चाय, पानी, नाश्ता और फलों के निःशुल्क सेवा स्टॉल लगाए जाएंगे।
इसके अलावा, आठ प्रवेश द्वारों पर आठ जूता-घर बनाए जाएंगे, जिनकी संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जाएगी।

जूता-घर सेवा अहंकार त्याग और विनम्रता की साधना का प्रतीक है—गुरु दरबार में प्रवेश से पहले बाहरी वैभव को त्यागने का संदेश देती है।

गतका प्रदर्शन और सांस्कृतिक आयोजन

समागम में सिखों की पारंपरिक युद्धकला 'गतका' का प्रदर्शन होगा, जिसमें शौर्य, अनुशासन और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा।
साथ ही, नौ समाजों द्वारा कीर्तन, कथा और धार्मिक प्रवचनों का आयोजन किया जाएगा, जिससे गुरु साहिबजी के जीवन और बलिदान का संदेश नई पीढ़ी तक पहुंचेगा।

विशेष यात्रा, टेंट सिटी और पुष्पवृष्टि

दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, मुंबई और हैदराबाद से निःशुल्क विशेष रेल सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, साथ ही दोनों दिनों के लिए विशेष विमान सेवाएं भी रहेंगी।
कार्यक्रम स्थल पर 10,000 श्रद्धालुओं के लिए सुविधायुक्त टेंट सिटी बनाई जा रही है।

इसके अलावा, हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्पवृष्टि की जाएगी, जो श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक होगी।

सेवा से इतिहास के साक्षी बनें

नांदेड में होने वाला यह 350वां शहीदी समागम केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सेवा, समानता, बलिदान और मानवता का महोत्सव है।
गुरु तेगबहादूर साहिबजी का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है और यह आयोजन पूरे विश्व को एक बार फिर सही दिशा देने का कार्य करेगा।

इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, बागेश्वर के आचार्य, महंत और अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।

आइए,
इस गौरवशाली आयोजन के साक्षी बनें,
सेवा में सहभागी हों
और गुरु चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें।

(विशेष लेख | 14 जनवरी 2026),
अलका पाटील,
उपसंपादक,
जिमाका, नांदेड.
(स्रोत ज़िला माहिती कार्यालय नांदेड़)

महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ

नंदिग्राम टाईम्स

Thursday 15th January 2026 वर्ष - 9, अंक 260 , पृष्ठ 03

अकोला महापालिका चुनाव: मुस्लिमबहुल वार्डों में कांग्रेस-एमआईएम के बीच कड़ी टक्कर, 13 सीटों पर संघर्ष

अकोला महानगरपालिका चुनाव में मुस्लिमबहुल वार्डों में इस बार कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। इन वार्डों को कांग्रेस की मजबूत बस्तियाँ माना जाता था, जहां 2017 के चुनाव में पार्टी ने कई सीटें जीत रखी थीं।

इस बार कुल 13 सीटों पर कांग्रेस को एमआईएम की चुनावी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एमआईएम ने अधिकतर मुस्लिम बहुल वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। खासकर वार्ड क्रमांक 1, 2, 7, 8, 9, 11, 17 और 18 जैसे इलाकों में दोनों पार्टियों के उम्मीदवार आमने-सामने हैं।

कांग्रेस के लिए यह चुनौती इसलिए और गंभीर हो गई है क्योंकि एमआईएम के अलावा अन्य पार्टियाँ भी उम्मीदवार खड़े कर चुकी हैं, जिससे मत विभाजन का खतरा बढ़ गया है। परिणामस्वरूप कांग्रेस को अपनी पारंपरिक वोट बैंक बचाने में कठिनाई हो सकती है। इस कड़ी टक्कर के बीच अकोला के मतदाता यह तय करेंगे कि क्या कांग्रेस अपनी पकड़ बरकरार रख पाती है या एमआईएम इस चुनावी क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति बना लेती है।

NANDED NEWS | "तू प्रचार कैसे करता है? तेरा भी बियाणी कर देंगे।"

नांदेड महापालिका चुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार सरिका भालेराव के पति पर तलवार से हमला — सीसीटीवी में कैद हुईं भयावह सूरत

नांदेड — नांदेड वाघाळा महानगरपालिका चुनाव के ठीक पहले एक भयावह और चिंताजनक घटना सामने आई है, जिसने स्थानीय राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना कांग्रेस पार्टी की महिला उम्मीदवार सरिका भालेराव के घर के पास हुई, जब उनके पति शिवाजी भालेराव पर अज्ञात हमलावरों ने तलवार से जानलेवा हमला करने की कोशिश की। इस पूरी घटना का एक अंश सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुआ है।

घटना प्रभाग क्रमांक एक में मंगलवार रात इस समय घटी जब चुनाव प्रचार का शोर थम चुका था और प्रचार सामग्री समेटी जा रही थी। शिवाजी भालेराव अपने मित्र के साथ बैठे थे, तभी कुछ अज्ञात हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उन पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने तलवार और लाठियों का इस्तेमाल करते हुए उन पर वार करने की कोशिश की। सौभाग्य से शिवाजी ने तुरंत अपनी कुर्सी को पटका और तलवार का वार चकमा दे दिया, अन्यथा परिणाम और भी गंभीर हो सकता था।

सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि हमलावरों के बीच एक व्यक्ति तलवार लेकर आगे बढ़ रहा है, जबकि दूसरे लोग हथियारों के साथ खड़े हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोग और स्थानीय निवासियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया, जिससे कुछ हमलावर भागने में सफल रहे। पुलिस ने तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और फुटेज की सहायता से संदिग्धों की पहचान के प्रयास जारी हैं।

हमले के बाद अपने बयान में शिवाजी भालेराव ने कहा कि उन्हें धमकियाँ भी दी गईं, जैसे "तू प्रचार कैसे करता है? तेरा भी बियाणी कर देंगे।" उन्होंने कहा कि वे एक साधारण कार्यकर्ता हैं और जनता की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह की धमकी या हिंसा स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच करने और दोषियों को सज़ा दिलाने की मांग की है।

स्थानीय पुलिस ने इस घटना को राजनीतिक उत्पीड़न और चुनावी हिंसा का संभावित मामला बताया है और कहा कि पूरा मामला जांच के दायरे में है। पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है।

घटना के बाद कांग्रेस सांसद रविंद्र चव्हाण ने हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि चुनावी प्रक्रिया में इस तरह की हिंसा लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने प्रशासन से परिवार को सुरक्षा प्रदान करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

यह हमला महापालिका चुनाव के सिर्फ दो दिन पहले हुआ है, जो पहले से ही तनावपूर्ण चुनावी माहौल को और भी अधिक तंग और संवेदनशील बना रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक हिंसा और डर का माहौल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करेगा? प्रशासन और पुलिस जल्द से जल्द स्पष्ट और सख्त कार्रवाई करके जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदान शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से होगा।

मुंबई BMC चुनाव 2026: मराठा कार्ड बनाम विकास एजेंडा — 10 अहम बिंदु

संवाददाता |

मुंबई — 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव 2026 में मुख्य लड़ाई ठाकरे बंधुओं (शिवसेना-UBT & MNS) और माहायुति (भाजपा-शिंदे) के बीच "मराठी पहचान" बनाम "विकास एजेंडा" पर है। शिवसेना-MNS गठबंधन मराठी अस्मिता, स्थानीय रोजगार, मराठी मॉनूस की सुरक्षा और भावनात्मक मुद्दों पर जोर दे रहा है, जबकि माहायुति विकास, बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और बड़े आर्थिक प्रोजेक्ट्स को प्रमुखता दे रही है। बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निकाय है और इसका बजट कई राज्यों से बड़ा है।

शिवसेना-MNS गठबंधन मराठी पहचानों जैसे मराठी-भाषा-वर आधारित योजना, आवास, और स्थानीय कल्याण वादे कर रहा है, वहीं माहायुति AI आधारित अप्रवासी पहचान, बुनियादी ढांचे और रोजगार योजना की बात कर रहा है। वोटरों में युवा और शहरी आवाज़ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह चुनाव मुंबई की राजनीति और 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा भी तय कर सकता है।

भारत में कैदी चुनाव लड़ सकते हैं पर मतदान का अधिकार नहीं — ज़मानत-तड़ीपार आरोपी के लिए नियम स्पष्ट

लातूर — लोकतंत्र के मूलाधार मतदान और चुनावी प्रतिनिधित्व के बारे में कानून ने स्पष्टकिया है कि कैदी चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन वोट नहीं डाल सकते। यह जानकारी लातूर से प्रकाशित एक रिपोर्ट में सामने आई है, जिसमें गुन्हेगारी पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की चुनावी पात्रता को प्रमुख विषय बनाया गया है।

भारतीय लोकप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के अनुच्छेद 62(5) के तहत, जो व्यक्ति प्रत्यक्ष तौर पर जेल में बंद है, वह किसी चुनाव में मतदान नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि कोर्ट में चल रहे मामलों में याचिकाकर्ता या आरोपी कैदियों को मतदान का अधिकार नहीं मिलता, भले ही वे किसी चुनावी मैदान में उम्मीदवार के रूप में भाग ले सकें।

दिलचस्प रूप से, कानून में इस स्थिति का विरोधाभास भी दिखता है: वहीं जहां जेल में बंद व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकता है, अर्थात उसने नामांकन दाखिल किया है, वहाँ वह मतदान का अधिकार खो देता है क्योंकि वह 'मतदाता' (elector) नहीं माना जाता।

दूसरी ओर, ज़मानत पर रिहा आरोपी और तड़ीपार (externed) व्यक्ति के मामले में नियम अलग हैं। ज़मानत पर होने पर व्यक्ति सामान्य मतदाता की तरह मतदान कर सकता है क्योंकि वह जेल में नहीं है। इसी तरह, तड़ीपार व्यक्ति को अपने मतदाता केंद्र पर निश्चित समय सीमा के भीतर पहुँचकर मतदान करने की अनुमति दी जाती है, हालांकि उसके बाद उसे फौरन अपने मूल स्थान पर लौटना होता है।

राज्य कारागृहों में बंद कैदियों के बीच यह विषय खासा चर्चित है, विशेषकर जब लोकतंत्र का उत्सव चुनाव के समय सामान्य नागरिकों का मताधिकार और उसकी सीमाएं लोगों के सामने आते हैं। चुनाव आयोग की इससे जुड़ी व्यवस्था और कानूनी नियम नागरिकों को यह समझने में मदद देते हैं कि कौन मतदान का हकदार है और कौन नहीं।

औसा नगरपरिषद में ऐतिहासिक 'बहन-भाई' शासन: परवीन शेख नगराध्यक्ष, डॉ. अफसर शेख उपनगराध्यक्ष

लातूर जिले के औसा नगरपरिषद में स्थानीय नगरपालिका चुनाव के बाद एक ऐतिहासिक 'बहन-भाई' नेतृत्व का दौर शुरू हुआ है। मंगलवार को आयोजित विशेष सभा में पहली बार नगराध्यक्ष के रूप में परवीन शेख और उपनगराध्यक्ष के रूप में उनके भाई डॉ. अफसर शेख का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। यह आयोजन उत्साह और धार्मिक भावना के साथ संपन्न हुआ, जिससे स्थानीय जनता में खुशी की लहर दौड़ गई।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के पैनल ने 23 में से 17 सीटें जीतकर नगरपरिषद में अपना दबदबा कायम किया है। सभा का संचालन खुद महापौर परवीन शेख ने किया, जबकि डॉ. अफसर शेख को उपमहापौर पद के लिए चुना गया। इसके अलावा, हमीद सय्यद और जुनेद सय्यद को भी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे अनुभव और युवा नेतृत्व का संतुलन बना है। चुनाव जीतने के बाद डॉ. अफसर शेख ने कहा कि उनके प्रशासन का लक्ष्य शहर के संतुलित विकास, स्वच्छता, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर विशेष ध्यान देना है। स्थानीय लोगों ने नए नेतृत्व का स्वागत किया और शहर के भविष्य को लेकर आशावादी नजर आए।

साजिदा शेख: उद्धव ठाकरे-शिवसेना की प्रमुख मुस्लिम महिला नेता BJP में शामिल

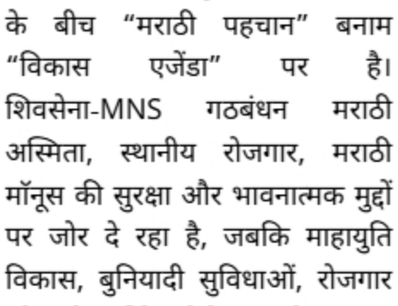

मुंबई — साजिदा शेख, जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) की प्रमुख मुस्लिम महिला चेहरे के रूप में उभर चुकी थीं, ने मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2026 से ठीक पहले पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) जॉइन कर लिया है। यह कदम चुनावी रणभूमि में गणतंत्रवादी राजनीतिक मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि साजिदा मुस्लिम समुदाय में एक प्रभावशाली आवाज मानी जाती हैं और उनका BJP में शामिल होना पार्टी के लिए अल्पसंख्यक वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

साजिदा ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास" के दृष्टिकोण से प्रेरित हैं, और अब BJP के चुनावी मिशन को समर्थन देंगी। उनका यह राजनीतिक बदलाव BMC चुनाव के समीकरणों को प्रभावित कर सकता है, खासकर मुंबई की मुस्लिम-बहुल सीटों पर जहां साजिदा की सामाजिक और राजनीतिक पकड़ रही है।

छत्रपती संभाजीनगर में चुनावी राजनीति का हाई-वोल्टेज ड्रामा: तनाव, क्रोध और सुलह का दौर

छत्रपती संभाजीनगर — महानगरपालिका 2026 के चुनावी अभियान ने शहर में उच्च-वोल्टेज राजनीति का मंजर पेश किया, जिसमें तनाव, गुस्सा, क्रोध और सुलह के कई दृश्य देखने को मिले। प्रचार दो हफ्तों से चल रहा था और 13 जनवरी को एक तीव्र राजनीतिक धूमधड़ाका के बाद यह प्रचार थामा गया, तब तक शहरवासियों ने राजनीति का ड्रामाटिक अनुभव देखा।

प्रचार के दौरान आंतरिक कलह, नाराजगी और बगावत ने राजनीतिक गलियारों को हिलाया। कई नेताओं के वाहन घेर दिए गए, पोस्टर फाड़े गए और कुछ प्रचार कार्यालयों में तो उपोषण और शिवीगाल जैसी घटनाएँ भी हुईं। कुछ नेताओं ने घरों-द्वारों पर जाकर बगावत को शांत करने की कोशिशें कीं, जिससे राजनीति में चरम तनाव पैदा हुआ।

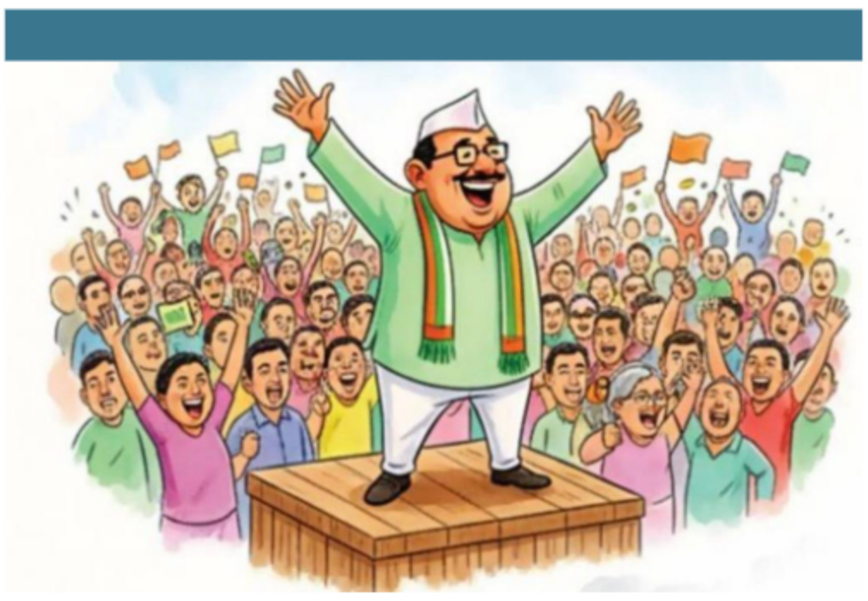

उम्मीदवार न मिलने पर कई कार्यकर्ता बी-फॉर्म बदल कर दूसरे दलों के साथ हो लिए, जिससे प्रमुख दलों के मतों का गणित बिगड़ा और यह चुनाव रिक्तियों तथा गठबंधनों की बैठकों का विषय बन गया। कई गुटों द्वारा गठबंधन की कोशिशों के बावजूद कोई ठोस समझौता नहीं हो सका,

जिससे प्रचार मांगलिक बैठकों और चर्चा-विवाद से भरा रहा। आखिरकार 2 जनवरी से चल रही यह रणधूम मंगळवार को शांत हुई और मतगणना से पहले नागरिकों ने राहत की सांस ली। अब 14 जनवरी को शांतिपूर्वक संक्रांति का उत्सव मनाने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं।

मीरा-भायंदर महापालिका चुनाव: संभावित धार्मिक विवाद के बीच सुरक्षा बढ़ाने की मांग, मंत्री सरनाइक ने लिखा पत्र

मीरा-भायंदर (नवी मुंबई) — आगामी मीरा-भायंदर नगर निगम चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करने के प्रयास के बीच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने संभावित धार्मिक विवाद और तनाव भड़काने की आशंका जताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की सख्त मांग की है। मंत्री ने कहा है कि शहर में सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों के दौरान कुछ समाजकंटक समूह धार्मिक, जातीय और भाषा-आधारित तनाव फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना प्रभावित हो सकती है। इसीलिए उन्होंने पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक व महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा को लेखी निर्देश जारी कर सुरक्षा-बंदोबस्त और निगरानी बढ़ाने का आग्रह किया है।

सरनाइक ने पत्रकारों को बताया कि शहर, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर रहा है और "मिनी भारत" के रूप में जाना जाता है, वहाँ कुछ असामाजिक तत्व समय-समय पर विवाद उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि धार्मिक स्थलों के आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम, सीसीटीवी निगरानी और जन सामान्य के लिए शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्हें यह भी चिंता है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री फैलने से माहौल और बिगड़ सकता है, अतः उस पर भी विशेष नियंत्रण रखा जाना चाहिए।

मंत्री सरनाइक ने प्रशासन से यह भी कहा कि इन संभावित तनाव के स्रोतों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भावना बनी रहे और नागरिक निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। यह समाचार मीरा-भायंदर स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच सुरक्षा और सामाजिक सामंजस्य की महत्ता को उजागर करता है।

नांदेड़ वॉक्स

नांदेड़ जिला > नांदेड़ शहर

नंदिग्राम टाईम्स

Thursday 15th January 2026 वर्ष - 9 , अंक 260, पृष्ठ 04

स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार 2025 के लिए प्रविष्टि व पुस्तकें भेजने की अंतिम तिथि घोषित

नांदेड, 14 जनवरी (स्रोत ज़िमाका,नांदेड़) — मराठी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र शासन की ओर से दिए जाने वाले स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार 2025 के लिए प्रविष्टि प्रपत्र (एंट्री फॉर्म) एवं पुस्तकों को भेजने की अवधि घोषित कर दी गई है। यह अवधि 1 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है।

इस पुरस्कार के लिए केवल वे पुस्तकें पात्र होंगी, जिनका प्रथम संस्करण 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच प्रकाशित हुआ हो। प्रतियोगिता हेतु प्रविष्टि प्रपत्र मुंबई शहर और मुंबई उपनगर को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों के जिलाधिकारी कार्यालयों में तथा महाराष्ट्र राज्य साहित्य और संस्कृति मंडल के कार्यालय में उपलब्ध हैं।

प्रतियोगिता से संबंधित विस्तृत नियमावली एवं प्रविष्टि प्रपत्र सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य और संस्कृति मंडल, रविंद्र नाट्यमंदिर भवन, द्वितीय मंज़िल, सयानी मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई–400025 के कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, मुंबई शहर और उपनगर को छोड़कर अन्य जिलों में संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय की सामान्य शाखा अथवा मनोरंजन शाखा में भी ये प्रपत्र उपलब्ध कराए गए हैं।

साथ ही, महाराष्ट्र शासन की आधिकारिक वेबसाइट www.maharashtra.gov.in के ‘नवीन संदेश’ और ‘What’s New’ अनुभाग में तथा महाराष्ट्र राज्य साहित्य और संस्कृति मंडल की वेबसाइट http://sahitya.marathi.gov.in पर भी प्रविष्टि प्रपत्र और नियम पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है।

लेखक अथवा प्रकाशकों को प्रविष्टि प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित अपनी पुस्तकें इस प्रकार भेजनी होंगी कि वे 30 जनवरी 2026 तक संबंधित कार्यालय में पहुंच जाएं।
मुंबई शहर एवं मुंबई उपनगर के लेखक/प्रकाशक अपनी पुस्तकों की दो प्रतियों सहित प्रविष्टि प्रपत्र सीधे महाराष्ट्र राज्य साहित्य और संस्कृति मंडल के कार्यालय में भेजें। जबकि अन्य जिलों के लेखक/प्रकाशक संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रविष्टि एवं पुस्तकें जमा करें।

प्रविष्टि एवं पुस्तकें भेजते समय बंद लिफाफे या पैकेट पर “स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार 2025 हेतु प्रविष्टि” ऐसा स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाली प्रविष्टियां स्वीकार नहीं की जाएंगी, यह जानकारी उपजिलाधिकारी (सामान्य), नांदेड द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है।

NWMC NANDED ELECTION 2026 | नांदेड महानगरपालिका चुनाव:

नांदेड महानगरपालिका चुनाव: 70 संवेदनशील बूथ, 4,000 कर्मचारी और 3,000 पुलिसकर्मी तैनात

नांदेड — आठ वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद नांदेड वाघाळा महानगरपालिका की महापालिका चुनाव प्रक्रिया 15 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने की अंतिम तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने इस चुनाव को लोकशाही का उत्सव बताते हुए सभी विभागों को चुस्त-दुरुस्त रखा है और मतदाता सुरक्षा तथा सुव्यवस्था पर विशेष फोकस किया गया है।

इस बार शहर में कुल 600 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 70 केंद्रों को संवेदनशील केंद्रों के रूप में घोषित किया गया है। इन विशेष केंद्रों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी ताकि किसी भी तरह की अनियमितता या उग्र प्रतिक्रिया को रोका जा सके।

प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि चुनाव प्रक्रियाएँ निर्बाध रूप से चलें। इसके लिए लगभग 4,000 कर्मचारी और 60 क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त किये गए हैं जो सभी

मतदान केंद्रों पर ड्यूटी करेंगे। चुनाव विभाग ने 660 मतदान दलों का गठन किया है, जो मतदान सामग्री, मशीनों तथा मतदाताओं से संबंधित हर जरूरत का ध्यान रखेंगे।
सुरक्षा के लिहाज से, 3,000 से अधिक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे, जिसमें स्थानीय पुलिस के साथ-साथ बाहरी जिलों से बुलाए गए 1,481 जवान भी शामिल हैं। इन सभी को 210 वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तैनात किया गया है। साथ ही 1,350 होमगार्ड कर्मियों को भी व्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए लगाया गया है। इन संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा के तौर पर सीसीटीवी कैमरों और गश्त दलों की व्यवस्था रखी गई है, ताकि वोटिंग के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या न हो। प्रशासन ने यह भी साफ़ किया है कि कोई भी उग्र तत्व या समस्या पैदा कर सकता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मतदाता सुविधा के लिए भी विशेष इंतज़ाम किये गये हैं। बूथों पर सहज पहुँच के लिए रैम्प, व्हीलचेयर सुविधा, बुज़ुर्गों और दिव्यांगों के लिए प्राथमिक मदत, स्वच्छ पानी और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के साथ आए मतदाताओं को प्राथमिकता देने का आदेश भी जारी किया गया है।

प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे शांतिपूर्वक मतदान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गयी हैं और नांदेड महानगरपालिका के चुनाव को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने का पूरा भरोसा प्रशासन ने व्यक्त किया है।

गोदावरी मराठवाडा महामंडळ १४० उपविभाग बंद करेगा, खर्च कटौती पर जोर

संवाददाता |

छत्रपती संभाजीनगर — गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ ने खर्च में कटौती और आर्थिक दक्षता बढ़ाने के मकसद से एक बड़ा निर्णय लिया है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, महामंडळ को 1 अप्रैल 2026 से स्वायत्त बनाया जाएगा, जिससे वह अपने खर्च और राजस्व को खुद संभालेगा। उसी दिशा में कदम उठाते हुए महामंडळ के १४० उपविभाग (सब-डिवीजन) बंद करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
गोदावरी महामंडळ मराठवाडा के 10 जिलों में सिंचाई योजनाओं और धरणों के पाणी प्रबंधन का कार्य करता है। इन उपविभागों के संचालन पर खर्च अधिक होने और कुछ स्थानों पर शाखा अभियंता की रिक्तियों के चलते वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। अधिकारी कहते हैं कि अनावश्यक कार्यालयों को बंद करना और पानी पट्टी वसूली बढ़ाना स्वायत्तता के उद्देश्यों में शामिल है। इससे महामंडळ की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और मराठवाडा में सिंचाई सेवाओं की निरंतरता बनी रहेगी।

अकोला महापालिका चुनाव: शिंदे गट-शिवसेना ने वंचित बहुजन आघाडी से साधा समर्थन, बदल सकते हैं चुनावी समीकरण

अकोला — अकोला महानगरपालिका चुनाव के घाट पर राजनीतिक गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं, जिसमें शिंदे गट-शिवसेना ने वंचित बहुजन आघाडी (VBA) के प्रकाश आंबेडकर से समर्थन की अपील की है। इस रणनीति को कड़ी राजनीतिक चाल बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अन्य बड़े दलों के खिलाफ चुनावी विरोध को मज़बूत बनाना है।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, शिंदे गट की शिवसेना ने उन वार्डों में जहां वंचित बहुजन आघाडी उम्मीदवार नहीं हैं, वहाँ की वोटिंग VBA के पक्ष में बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य उन हिस्सों में अपनी पकड़ को सुदृढ़ करना है जहाँ प्रतिस्पर्धा कड़ी है। इस समर्थन के पीछे विचार यह है कि वंचित बहुजन आघाडी के समर्थक और वोट बैंक साँझा करने से शिंदे सेने को फायदेमंद परिणाम मिल सकते हैं।

इस संदर्भ में शिवसेना के मंत्री संजय राठोड और VBA के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर के बीच एक बैठक भी आयोजित हुई थी, जो शहर के बाहर गुप्त स्थान पर हुई। इस बैठक में राजनीतिक रणनीति, समर्थन के स्वरूप और चुनावी सहयोग के संभावित रूपों पर चर्चा हुई। स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भाजपा और एमआईएम के गठबंधन के खिलाफ एक रणनीतिक प्रतिक्रिया हो सकता है और इससे निष्कर्षों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

अकोला में इस चुनावी मौसम में कई दलों के बीच गठबंधनों और ब्रेकिंग मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। हाल में भाजपा-एमआईएम की अकोट नगर परिषद में गठजोड़ वाली खबरें भी चर्चा में हैं, जो स्थानीय राजनीति में तेजी से बदलते समीकरण को उजागर करती हैं।

वंचित बहुजन आघाडी की भूमिका भी अकोला चुनाव में महत्वपूर्ण बनी हुई है। पार्टी के पास अभी अपने उम्मीदवारों की संख्या सीमित है, इसलिए स्थानीय राजनैतिक रणनीतियाँ और गठबंधनों को लेकर सभी दल संभावित गठजोड़ों की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। अगर शिंदे-शिवसेना और VBA के बीच समर्थन का कोई औपचारिक समझौता होता है, तो इससे चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव आ सकता है।
विश्लेषकों का यह भी मानना है कि भाजपा-शिंदे सेना-VBA के बीच समर्थन की छड़छाड़ से अकोला महापालिका के चुनाव परिणामों पर काफी असर पड़ेगा, खासकर उन वार्डों में जहाँ मतदाता विभाजन अपेक्षित है। यह कदम यह संकेत देता है कि स्थानीय राजनीति में रणनीतिक गठबंधन, जनता के मुद्दों पर सहमति और वोट बैंक में बदलाव चुनाव के अंतिम परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं।
अंततः अकोला महापालिका चुनाव सिर्फ उम्मीदवारों के नामों पर टिका नहीं है, बल्कि यहाँ राजनीतिक गठबंधनों, स्थानीय हितों और वोट बैंक रणनीतियों के आधार पर निष्कर्ष तय होंगे। स्थानीय जनता चुनाव के समय इन सभी राजनीतिक खेलों को ध्यान से देख रही है ताकि उसके लिए सबसे अनुकूल परिणाम सामने आए।

फसल ऋण पर कोई स्टांप शुल्क नहीं, किसानों को बड़ी राहत

नांदेड : राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि फसल ऋण पर लगने वाले स्टांप शुल्क को पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। इसके तहत दो लाख रुपये तक के फसल ऋण से जुड़े सभी दस्तावेजों पर अब किसी भी प्रकार का स्टांप शुल्क नहीं देना होगा।

अब तक किसानों को ऋण करारनामे, गिरवी दस्तावेज, घोषणा पत्र और अन्य कागजातों पर स्टांप शुल्क चुकाना पड़ता था। दो लाख रुपये के ऋण पर करीब 300 से 600 रुपये तक का अतिरिक्त खर्च आता था। नई व्यवस्था से यह खर्च पूरी तरह समाप्त हो गया है, जिससे ऋण प्रक्रिया सरल और सस्ती होगी।

सरकार के इस फैसले से विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा। बढ़ती खेती लागत, बीज, खाद, कीटनाशक और मजदूरी के बीच यह निर्णय किसानों के लिए राहत भरा बताया जा रहा है।
मुद्रांक शुल्क अधिकारी महेश वडदकर ने बताया कि यह छूट अगले आदेश तक लागू रहेगी।

मुंबई में एटीएस ने दो बांग्लादेशी महिलाओं को अवैध रूप से रहने और पुनः प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार

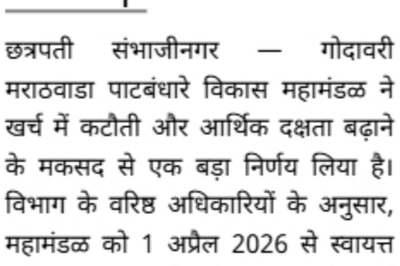

मुंबई — एंटी टेररिज़्म स्क्वॉड (ATS) और स्थानीय पुलिस ने बिलकिस बेगम सिरमिया अख्तर और ज़ुलेखा जमाल शेख नामक दो बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जो बिना वैध पासपोर्ट, वीजा या इमिग्रेशन दस्तावेज के शहर में अवैध रूप से रह रही थीं। दोनों को पहले भी अगस्त 2025 में भारत से डिपोर्ट किया जा चुका है, लेकिन वे फिर से अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर मुंबई में निवास कर रही थीं। पुलिस ने अब उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और विदेशी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
एटीएस को खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई, और जांच एजेंसियाँ इन महिलाओं के नेटवर्क और प्रवेश की प्रक्रियाओं का और विश्लेषण कर रही हैं ताकि संभावित जोखिमों और बड़े नेटवर्क का पता लगाया जा सके।

छत्रपती संभाजीनगर: मतदान-मतगणना के दौरान 5,000 पुलिसकर्मी 48 घंटे तैनात, सख्त सुरक्षा बंदोबस्त

छत्रपती संभाजीनगर — महानगरपालिका चुनाव के मतदान और मतगणना प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 5,000 पुलिसकर्मियों का 48 घंटे सख्त सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। मतदान से लेकर मतगणना तक शहर पुलिस 4,667 कर्मियों के साथ तैनात रहेगी, और आवश्यकतानुसार होमगार्ड सहित अतिरिक्त बैक-अप भी तैयार रखा गया है।

पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने वरिष्ठ अधिकारियों और थानेदारों के साथ पांच दिनों तक लगातार बैठकें कर सुरक्षा रणनीति तैयार की। संवेदनशील क्षेत्रों में 10 से अधिक ड्रोन निगरानी के लिए उड़ान भरेंगे, जबकि विशेष प्रशिक्षित साइबर पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। प्रशासन ने 283 ऐसे व्यक्तियों को मतदान-मतगणना समय के लिए प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है जिनका पिछली चुनावों में आपराधिक पृष्ठभूमि रही है।

मतदान केंद्रों और गिनती स्थलों के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, साथ ही आग्नेय सामग्री और तंबाकूजन्य पदार्थ रखने पर भी रोक रहेगी। केवल नियंत्रण अधिकारियों, उम्मीदवार प्रतिनिधियों और चुनाव कर्मियों वाले वाहनों को ही प्रवेश अनुमति दी जाएगी। पुलिस ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भय होकर लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें, अफवाहों पर विश्वास न करें और किसी भी असामान्य स्थिति की सूचना तुरंत सुरक्षा बलों को दें।

मतदान केंद्रों पर चक्कर आए तो तुरंत चिकित्सा सहायता, 250 स्वास्थ्यकर्मी तैनात

नांदेड महानगरपालिका चुनाव के दौरान मतदान और मतगणना केंद्रों पर मतदाताओं, कर्मचारियों तथा अधिकारियों की तबीयत बिगड़ने की स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारी की है। शहर के सभी मतदान केंद्रों पर प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध रहेगी, वहीं डॉक्टरों के साथ एंबुलेंस भी सतर्क अवस्था में तैनात रहेंगी।
महानगरपालिका के 20 प्रभागों की 81 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में कुल 5 लाख 1 हजार 799 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाएं तथा बीमार मतदाताओं को विशेष प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। मतदान के दौरान चक्कर आना, कमजोरी, ठंड या गर्मी से परेशानी जैसी शिकायतों पर तत्काल इलाज की व्यवस्था रहेगी।
इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के लिए स्वास्थ्य विभाग के 250 कर्मचारी कार्यरत रहेंगे। मतदान एवं मतगणना दोनों चरणों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। सभी स्वास्थ्य दलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाए।

महानगरपालिका स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस के साथ-साथ जिला शल्य चिकित्सक विभाग की एंबुलेंस भी मतदान के दिन सेवा में रहेंगी। इसके अतिरिक्त, आशा स्वयंसेविकाओं को प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर अटेंडेंट के रूप में तैनात किया गया है, ताकि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
हैदराबाद स्थित अस्पताल की ओर से दो स्वास्थ्य दल व एक एंबुलेंस तथा शिवाजीनगर अस्पताल की ओर से भी दो दल व एक एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने नागरिकों से निर्भय होकर मतदान करने की अपील की है।

स्वाधिकारी नंदिग्राम टाईम्स (नांदेड़) के मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक शेख जहूर शेख अहेमद द्वारा सहारा डिजाइनिंग एंड ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, वाजेगांव, ता. व जि. नांदेड़ में मुद्रित तथा दैनिक नंदिग्राम टाईम्स, मुल्लाह मार्केट, खवी बिल्डिंग, नगरेश्वर मंदिर, नांदेड़–431604 (महाराष्ट्र) के कार्यालय से प्रकाशित। RNI-MAHHIN/2016/69743 मोबाइल संपर्क: 9921100075 | Email: ntinfodesk@gmail.com (वाद-विवाद हेतु न्यायक्षेत्र: नांदेड़ न्याय कक्षा में।)